Incentives to Eco-Friendly Agriculture

2718. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the increased demand of food made from Eco-friendly agricultural products/technology and practices;

(b) whether it is a fact that pesticides are being replaced with natural eco-friendly products with highly satisfactory results with socio economic advantages apart from environmental ecological advantages; and

(c) whether it is also a fact that the Ministry of Agriculture is advocating heavy use of chemicals through heavy subsidies and other incentives and also disincentives to ecological farming and if so whether a high level dialogue will be held with that Ministry to bring them in line with the world trends which incidentally are also being supported by Department of Biotechnology and Dept. of Science & Technology and many NGOs in the country and abroad as also various Government especially in USA and Europe?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) Yes Sir. In order to minimise the use of chemical pesticides for pest control, Government is promoting Integrated Pest Management (IPM) technology where pesticides are used judiciously on need base. The Registration Committee constituted under the Insecticides Act has registered on provisional basis the use of neem based pesticides and biocides with a view to promote the use of non-chemical pesticides in IPM programme.

भूमिगत जल का प्रदूषण स्तर

2719. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमिगत जल के विभिन्न चरणों में प्रदूषण के स्तर का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई है; यदि हां, तो तथ्य तथा किन-किन एजेंसियों ने कौन-कौन से स्थानों में जांच की थी;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ स्थानों में लोगों को तालाबों का संदूषित जल पीना पड़ता है क्योंकि भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित कड़वा और पीने योग्य नहीं है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, तो उसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड ने क्षेत्रीय जल-विज्ञानीय सर्वेक्षणों और भूमि-जल निगरानी गतिविधियों के एक भाग के रूप में भूमि-जल का रासायनिक विश्लेषण किया है। यह प्रदूषण के प्रकार और मात्रा की शिनाख्त करने के लिए तथा शिनाख्त किए गए क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रदूषण के संभावित कारणों को खोजने के लिए समय-समय पर व्यापक भूमि-जल प्रदूषण संबंधी अध्ययन भी करता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक भूमि-जल गुणवत्ता मानचित्र तैयार करने की दृष्टि से कुछ शिनाख्त किए गए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में भूमि-जल के आवधिक विश्लेषण हेतु एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य-भूमि जल बोर्डों के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

भूमि-जल की रासायनिक गुणवत्ता पर उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि फरीदाबाद, लुधियाना, कानपुर, पाली और वाराणसी जैसे शहरों के कुछ स्थानिक पॉकेटों में भूमि-जल औद्योगिक बहिस्रावों से प्रभावित हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में लोग पेय जल के लिए असुरक्षित वैकल्पिक सतही जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।